

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

ग्राम्य विकास विभाग  
(जिला विकास कार्यालय)  
जनपद चमोली

मैनुवल संख्या- 08

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उनके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी ।

## प्रस्तावना

यह मैनुअल अथवा हस्त पुस्तिका संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अनुरूप विभाग को षासन तथा लोकतन्त्र के प्रति उत्तरदायी बनाने के साथ-साथ भ्रष्टाचार को रोकने एवं सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा रखने के उद्देश्य से तैयार की गयी है। अधिनियम के अध्याय-2 नियम-4 (1) (ख) में निर्दिष्ट 17 बिन्दुओं में से बिन्दु-01 के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग के विभागीय कार्यकलापों को इस हस्त पुस्तिका में समाहित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है ताकि जन प्रतिनिधियों के साथ-साथ आम जनमानस के समक्ष सूचना की पारदर्शिता बनी रहे। उत्तरांचल सूचना आयोग के निर्देशानुसार इन 17 बिन्दुओं/मैनुअलों का अलग-अलग मैनुअल बनाया जाना है, जो अपने में एक स्वतन्त्र जैदक सवदमद्ध मैनुअल होगा। इस प्रकार सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम्य विकास विभाग, जनपद-चमोली के सभी 17 मैनुअल बने हुए हैं, जिनमें से यह मैनुअल संख्या-08 कहलायेगा।

2- यह मैनुअल ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्राम्य विकास विभाग के कार्मिकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। विभागीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में मैनुअल में दी गयी कतिपय सूचना षासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार की गयी है और कतिपय सूचनाओं को इस आधार पर तैयार किया गया है कि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी आम नागरिकों को सरलतम रूप में प्राप्त हो सके। मैनुअल/पुस्तिका में यथासम्भव सरलतम षब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि आम नागरिकों को इसे समझने में आसानी रहे।

3- इस हस्त पुस्तिका में समाहित विशयों एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला विकास अधिकारी, चमोली/ सहायक लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। पुस्तिका में उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अतिरिक्त यदि अन्य किसी प्रकार की सूचना जो कि अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन हो, वह भी जिला विकास अधिकारी, चमोली/सहायक लोक सूचना अधिकारी की अनुमति से प्राप्त की जा सकती है। जो भी व्यक्ति/नागरिक इस अधिनियम के अधीन किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहेगा उसे अधिनियम की धारा-6 (1) में निहित व्यवस्था के तहत हस्तलिखित अथवा इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से हिन्दी भाशा में लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने तथा अधिनियम की धारा-7(5) में किये गये प्राविधान के अधीन षासन द्वारा निर्धारित षुल्क रूपये 10/- प्रति आवेदन पत्र नकद जमा करने पर आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना को निम्नानुसार अतिरिक्त षुल्क जमा करने पर 30 दिन की अधिकतम समय सीमा अन्तर्गत प्राप्त कर सकता है। सूचना उसी रूप में दी जा सकेगी जिस रूप में विभाग द्वारा रखी जाती है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एक साथ अथवा एक ही प्रपत्र पर संकलित कर आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। इसलिए विभाग के पास विभागीय सूचना जिस रूप में होगी उसी रूप में आवेदित व्यक्ति/नागरिक को उपलब्ध करायी जा सकेगी। षासन से निर्धारित षुल्क का विवरण निम्न प्रकार है :-

(1) तैयार की गयी सामग्री अथवा किसी अभिलेख की छायाप्रति 14 या 13 साइज के कागज

पर एक पृष्ठ की रू0 2 (दो) प्रति पेज की दर से भुगतान करने पर।

(2) बड़े आकार के कागज में प्रतिलिपि दिये जाने पर उसकी वास्तविक लागत के समतुल्य धन0।

(3) अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए प्रथम एक घंटे के लिए कोई षुल्क देय नहीं होगा। एक

घंटे के पश्चात् प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके किसी भाग हेतु 5(पाँच) रुपये की दर से शुल्क

देय होगा।

(4) डिस्क्रेट/फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए 50 रुपये प्रति डिस्क्रेट/फ्लॉपी देय होगी।

(5) सैम्पल/मॉडल की दृष्टि में उसकी वास्तविक लागत का भुगतान करना होगा।

4- उक्तानुसार निर्धारित शुल्क लोक सूचना अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी या कर्मचारी के पास जमा कर उसकी प्राप्ति रसीद कोशागार प्रपत्र 385 पर प्राप्त की जा सकती है।

□□□□□□□□□□

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उनके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी ।

ग्राम्य विकास विभाग एक षासकीय विभाग है। विभाग को अपने जनपदीय , खण्ड स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय कार्मिकों के माध्यम से ही विभागीय कार्यक्रमों को क्रियान्वित कराना होता है। ग्राम्य विकास विभाग में प्रत्यक्ष रूप से कोई बोर्ड, परिषद एवं समिति अथवा निकाय गठित नहीं है। किन्तु त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत विभाग को ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के, खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत के तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत के प्रशासनिक नियन्त्रण में रखते हुए कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन पंचायतों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है।

73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ग्राम स्तर पर 1- नियोजन एवं विकास समिति 2- शिक्षा समिति 3- निर्माण कार्य समिति 4- स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति 5- प्रशासनिक समिति तथा 6- जल प्रबन्धन समिति गठित की गयी है। इसी प्रकार की समितियाँ क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत स्तर पर भी गठित हैं। इन समितियों में क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों पर चर्चाएँ होती हैं तथा सुझाव दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम स्तर पर वर्ष में कम से कम 2 खुली बैठकें, जिनमें आम जनता भाग लेती हैं, आयोजित की जाती हैं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर भी तिमाही बैठकें आयोजित होती हैं, जिसमें सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम प्रधान भाग लेते हैं। क्षेत्र पंचायत का पदेन सचिव, खण्ड विकास अधिकारी होता है। इस प्रकार जनता के प्रतिनिधि ही इन समितियों के सदस्य होते हैं। फलस्वरूप इसमें जनता की पूर्ण भागीदारी निहित होती है।

□□□□□□□□□□